of this Ministry. During the period 1-4-87 to 11-2-94, 221 cases of non-compliance of the above mentioned instructions were brought to the notice of this Department out of which 204 cases have since been settled. The concerned authorities have been directed at appropriate level to ensure immediate settlement of pending cases.

Committee's report on austerity measures

1494. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a high level committee headed by the then Cabinet Secretary Rajgopal was asked to submit a report on austerity measures, reducing Government flab and cutting down on top official posts; and

(b) if so, what are the recommendations of the committee and to what extent the recommendations of the Committee have been implemented for austerity measures ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA) : (a) It is not a fact that a high level committee headed by the then Cabinet Secretary Shri Rajagopal was asked to submit a report on austerity measures, and cutting down of top posts in Government. However, a committee comprising the Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat; Secretary (Expenditure), Establishment Officer & Additional Secretary, Department of Personnel & Training and Additional Secretary (Expenditure) did review the posts of the level of Joint Secretary/equivalent with a view to identifying posts for surrender and to bringing about a reduction in expenditure.

(b) Having regard to the recommendations of the Committee, the Government decided to abolish 52 posts at the level of Joint Secretary in a gradual manner; 48 such posts have since been abolished.

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल की आपूर्ति

1495. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा जन जाति क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु सातवीं योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए आठवीं योजना के दौरान जिलेवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) इस राज्य में सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिलेवार कितने-कितने गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए पेयजल सप्लाई हेतु, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कवरेज के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। 1988-89 और 1989-90 के शेष दो वर्षों के लिए लक्ष्य तथा पूरी योजना अवधि के दौरान उपलब्धि निम्न प्रकार है :

अनुसूचित जाति/जनजाति ग्रामीण जन संख्या (लाख में)

लक्ष्य		उपलब्धि	
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
7.96	11.44	22.68	34.82